सुरजीत सिंह और ए. एन. आर

बनाम

पंजाब राज्य

18 मई, 2007,

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

दंड संहिता,1860-एस.एस. 302,148,149 और 450-स्थिरता के तहत दोषसिद्धि- अभियोजन मामले मे मृतक की हत्या में अभियुक्त की भूमिका साबित नहीं हुई, इस प्रकार, धारा 302 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है- हालाँकि, अभियुक्त ने आपराधिक अतिचार किया, गैरकानूनी सभा का गठन किया और उसका बीमार उद्देश्य था लेकिन वह उसकी प्रकृति से साबित नहीं हुआ-इस प्रकार, धारा 450 और अन्य धाराओं के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई- अभियुक्त ने लगभग 5 साल का कारावास काटा है, अभियुक्त ने लगभग 5 वर्ष कारावास की सजा काट ली है, इसलिए उसे पहले ही काट ली गई अवधि के लिए कारावास की सजा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार उस दिन अपीलकर्ता और आदेश के सह-आरोपी पुलिसकर्मी बलपूर्वक एच लेबरर के घर में घुस गए, एच के बेटे एमएस ने भी इसे देखा। उसने खिड़की से देखा कि उसकी मां

बिना सलवार के लेटी हुई थी और आरोपी एलएस अपनी पतलून पहनने की प्रक्रिया में था, घटना को देखकर एमएस चिल्लाया लेकिन आरोपी डीएस ने उसे धमकी दी कि अगर वह चिल्लाया तो उसे जान से मार दिया जाएगा इसके बाद एसआर ने उसे मारने के लिए कहा और एचएस ने एच के सिर पर वार किया, जिससे एच की मौत हो गई, आरोपी भाग गया, एफआईआर दर्ज की गई, अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302/148/149/450 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा, इसलिए वर्तमान एसएस और डीएस द्वारा अपील की गयी।

न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत किया।

अभिनिर्धारित किया 1.1. निचली अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और प्राथमिकी में दिए गए बयान को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर विश्वास किया जाता है। उसके द्वारा दिए गए कारणों से सहमति है। [पैरा 6] [325-ए]

1.2. ऐसा लगता है कि आरोपी एच के साथ बलात्कार करने में सफल नहीं हुए क्योंकि उसके बेटे मदद के लिए चिल्लाने लगे। जहाँ तक एच की मृत्यु के आरोप का संबंध है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एच की हत्या में अपीलार्थियों की कोई भूमिका थी। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि, अन्य प्रावधानों

के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि बरकरार है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थियों ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक अतिचार किया। मृतक के घर में एक गैरकानूनी सभा भी बनाई, हालांकि इस तरह मृतक के बेटों की उपस्थिति से प्रयास असफल था। वे निश्चित रूप से एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य, हालांकि इसकी प्रकृति का पता नहीं था और न ही साबित कर दिया। अतः धारा 450 आई. पी. सी. पूरी तरह संतुष्ट है। अतः विचारण न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थियों को धारा 450 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया।

[पैरा 7,8 और 9] [325-बी, सी, डी, ई]

1.3. अपीलार्थी पहले ही लगभग 4 या 5 साल के कारावास की सजा काट चुके हैं और इसलिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा में पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए कारावास की सजा का विकल्प।[पैरा 10] [325-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 644/2006.

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.12.2005 से 2002 की आपराधिक अपील सं. 9-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

अपीलार्थियों के लिए बिमल रॉय, सुनीता पंडित और बी. के. खुराना।

प्रतिवादी की ओर से कवालजीत कोचर और अरुण के. सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

मार्कंडेय काटजू, जे.

1- यह अपील आपराधिक अपील संख्या 9-डीबी/2002 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 1.12.2005 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ताओं की अपील दिनांक 6.12.2001 को खारिज कर दिया गया है और धारा 302 / 148 / 149 / 450 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया है।

2. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

3. ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस मामले में पांच आरोपी थे, लेकिन यह अपील केवल दो आरोपियों, आरोपी नंबर 3 सुरजीत सिंह, ज्ञान सिंह के बेटे और आरोपी नंबर 5 दलजीत सिंह, के बेटे की ओर से दायर की गई है। आसा सिंह. उल्लेखनीय है कि एक अन्य सह-आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ बग्गा है जो कतार सिंह का बेटा है, लेकिन हमें इस मामले में उससे कोई सरोकार नहीं है। आपको यह भी बता दें कि पांचों सह-आरोपी पुलिसकर्मी हैं।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक हरबंस कौर अपने बेटों मोहन सिंह और रतन सिंह के साथ गांव बेरी में रहती थी। आरोप है कि 21.2.1997 को शाम लगभग 6 बजे हरबंस कौर आराम करने के लिए बाहर गई थी तभी आरोपी ने उससे कुछ अभद्र शब्द कहे और वह अपने घर लौट आई। उस समय मृतक हरबंस कौर का बेटा मोहन सिंह बाहर खेत में था और जब वह घर आया तो उसने अपने छोटे भाई को पहले से ही घर में पाया। मोहन सिंह ने आरोपियों को अपने घर आते देखा और उनका पीछा किया। उसने घर में कुछ चीखने की आवाज सुनी और खिड़की से देखा कि उसकी मां बिना सलवार के लेटी हुई थी और आरोपी लखविंदर सिंह अपनी पतलून पहनने की प्रक्रिया में था। उस वक्त उक्त कमरे में सभी आरोपित मौजूद थे. यह देखकर मोहन सिंह चिल्लाया लेकिन बताया जाता है कि आरोपी दलजीत सिंह ने उसकी ओर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि अगर चिल्लाया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। करतार सिंह के बेटे सुरजीत सिंह उर्फ बग्गा ने कथित तौर पर कहा कि अगर हरबंस कौर जिंदा रही तो वह सभी आरोपियों को फंसा देगी और इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। आरोप है कि इसके बाद हरिंदरजीत सिंह ने हरबंस कौर के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि हरबंस कौर का शव आंगन में फेंककर आरोपी भाग गए। आरोप है कि इसके बाद हरिंदरजीत सिंह ने हरबंस कौर के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि हरबंस कौर का शव आंगन में फेंककर आरोपी भाग गए। आरोप है कि इसके बाद हरिंदरजीत सिंह ने

हरबंस कौर के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि हरबंस कौर का शव आंगन में फेंककर आरोपी भाग गए।

5. उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.2.1997 की एफआईआर में मोहन सिंह के छोटे भाई रतन सिंह द्वारा दिया गया बयान ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों के बयान से अलग है। प्राथमिकी में सिर्फ इतना कहा गया है कि शाम करीब छह बजे जब रतन सिंह घर लौटा तो उसने अपनी मां हरबंस कौर का शव आंगन में पड़ा देखा. एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं था और उसमें दिए गए संस्करण से संकेत मिलता है कि किसी ने भी हमलावरों को नहीं देखा। हालाँकि, जैसा कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सही कहा था, सभी आरोपी पुलिसकर्मी थे, जबकि मृतक के परिवार गरीब मजदूर हैं। एफआईआर पर रतन सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो उस समय केवल 12 वर्ष के थे। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह ने जानबूझकर झूठी एफआईआर बनाई है, जिसमें आरोपी का नाम नहीं है क्योंकि वह उसी विभाग से हैं। पुलिस विभाग और इसलिए वह आरोपियों की मदद करना चाहता था। 14.4.1994 को जब मोहन सिंह (पीडब्लू1) एक आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर बहस सुनने गए तो उन्हें पता चला कि एफआईआर में आरोपियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी दिन उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत पत्र भेजकर कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष

जांच नहीं कर रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 17.4.1997 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की। पुलिस केस और आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। पुलिस विभाग और इसलिए वह आरोपियों की मदद करना चाहता था। 14.4.1994 को जब मोहन सिंह (पीडब्लू1) एक आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर बहस सुनने गए तो उन्हें पता चला कि एफआईआर में आरोपियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी दिन उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत पत्र भेजकर कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 17.4.1997 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की। पुलिस केस और आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। पुलिस विभाग और इसलिए वह आरोपियों की मदद करना चाहता था। 14.4.1994 को जब मोहन सिंह (पीडब्लू1) एक आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर बहस सुनने गए तो उन्हें पता चला कि एफआईआर में आरोपियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी दिन उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत पत्र भेजकर कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 17.4.1997 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की। पुलिस केस और आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। 1994 जब मोहन सिंह (पीडब्लू1) एक आरोपी द्वारा

दायर जमानत अर्जी पर बहस सुनने गए तो उन्हें पता चला कि एफआईआर में आरोपियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी दिन उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत पत्र भेजकर कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 17.4.1997 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की। पुलिस केस और आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। 1994 जब मोहन सिंह (पीडब्लू1) एक आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर बहस सुनने गए तो उन्हें पता चला कि एफआईआर में आरोपियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसी दिन उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पंजीकृत पत्र भेजकर कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 17.4.1997 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की। पुलिस केस और आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई।

6. हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों के संस्करण पर विश्वास करने के इच्छुक हैं और हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के लिए एफआईआर में दिए गए संस्करण को खारिज करने में उच्च न्यायालय से सहमत हैं।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी हरबंस कौर के साथ बलात्कार करने में सफल नहीं हुए क्योंकि उनके बेटे मोहन सिंह और रतन सिंह मदद के लिए चिल्लाए। जहां तक हरबंस कौर की मौत के आरोप का संबंध है, अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है, यह है कि सुरजीत सिंह उर्फ बग्गा, करतार सिंह का पुत्र (ज्ञान सिंह का पुत्र सुरजीत सिंह नहीं, जो अपीलकर्ता नंबर 1 है) हमारे सामने) ने उकसाया कि हरबंस कौर को मार दिया जाना चाहिए, और उसके बाद एक अन्य सह-अभियुक्त हरिंदरजीत सिंह ने हरबंस कौर के सिर पर घातक वार किया। इस प्रकार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे सामने अपील करने वालों की हरबंस कौर की हत्या में कोई भूमिका थी। सामान्य इरादे का भी कोई सबूत नहीं था. इसलिए, आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती और उन्हें खारिज किया जाता है।

8. हालाँकि, हम ट्रायल कोर्ट के फैसले में उल्लिखित अन्य प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखते हैं क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ हरबंस कौर के घर में आपराधिक अतिक्रमण किया और एक गैरकानूनी सभा भी बनाई। हालाँकि, मोहन सिंह और रतन सिंह की उपस्थिति से ऐसा प्रयास विफल हो गया था।

9. अपीलकर्ता अन्य साथियों के साथ मृतक के घर में घुस गया। निश्चित रूप से उनका कोई गलत उद्देश्य था, हालाँकि इसकी प्रकृति सिद्ध नहीं हुई है। हालाँकि, इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, यह ज्ञात नहीं था। हालाँकि, उसके घर में जबरन प्रवेश की बात साबित हो गई है। इस प्रकार, इस प्रकृति के मामले में आईपीसी की धारा 450 की सामग्री पूरी तरह से संतुष्ट है। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ताओं को उक्त प्रावधान के तहत अपराध करने का दोषी पाया है।

10. हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता पहले ही लगभग 4 या 5 साल की कैद काट चुके हैं और इसलिए हम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पहले ही भुगती गई अवधि के लिए कारावास की सजा से प्रतिस्थापित करते हैं। जब तक किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यक न हो, अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

11. इन टिप्पणियों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता जिंदोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।